



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

असाधारण

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 1981/21 फाल्गुन, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन खेती एवं परिवेश संरक्षण विभाग

आदेश

शिमला-171002, 25 फरवरी, 1981

संख्या 15-4/71-एस०एम०-2.—जबकि, राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के अन्तर्गत उचित जांच पड़ताल के पश्चात सन्तुष्ट है कि इस आदेश में अन्तर्विष्ट विनियम, निर्बन्धन, प्रतिषेध या निदेश इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु आवश्यक है।

2. अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 28) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (नगर निगम या नगर पालिका, अन्य स्थानीय निकायों के क्षेत्रों और ऐसी स्थानीय निकायों की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर) उन समस्त क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश सरकार की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 27-8-80 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, किन्नौर जिले में निम्न दर्शाये गए ढंग से इस आदेश के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित

होने की तिथि से 30 वर्षों की अवधि हेतु निम्न कार्यहेतु अस्थाई रूप से विनियमन, निर्बन्धित और प्रतिबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- (1) ऐसे क्षेत्रों से वृक्षों या इमारती लकड़ी का काटाना और उनका हटाया जाना प्रतिबद्ध होगा: परन्तु वन उत्पाद के सद्भाविक घरेलू उद्देश्यों हेतु ईन्धन और चारे पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा: परन्तु और यह कि स्वामी अपने सद्भाविक घरेलू तथा खेती सम्बन्धी प्रयोग के लिए प्रत्येक वर्ष पांच वृक्ष बिना किसी की आज्ञा के, दस वृक्षों तक सम्बन्धित परिक्षेत्राधिकारी की लिखित आज्ञा से तथा दस वृक्षों से अधिक सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी की लिखित आज्ञा से काट सकता है:

परन्तु और यह कि विक्रय हेतु वृक्षों का कटान 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा, जो कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया जायेगा कि प्रत्येक वर्ष इमारती लकड़ी तथा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले 50 वृक्षों तक का गिरान सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, 100 वृक्षों तक का गिरान अरण्यपाल, 200 वृक्षों तक का गिरान मुख्य अरण्यपाल तथा 200 वृक्षों से अधिक का गिरान राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात किया जायेगा तथा अन्य वृक्षों के लिए 10 वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अनुसार वन मण्डल अधिकारी अनुमति देगा:

आगे यह भी उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह घरेलू या खेती के कार्यों के लिए अथवा विक्रय हेतु वृक्ष गिराता है तो उसे एक वृक्ष गिराने पर कम से कम 3 वृक्ष रोपित करने होंगे। यदि ऐसे क्षेत्र में फल उद्यान लगाया जाता है तो इस सारे क्षेत्र में बगीचा राज्य उद्यान विभाग द्वारा निश्चित प्रतिमानों के अनुसार ही लगाया जायेगा।

- (2) पैरा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वन उत्पादन का निष्कासन, एकत्रीकरण या उसे हटाया या उसके किसी प्रकार की निर्माण प्रक्रिया प्रतिबद्ध होगी:

आगे यह भी उपबन्धित है कि बिरोजा निस्सारण कार्य, सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी की लिखित आज्ञा से मुख्य अरण्यपाल द्वारा समय-समय पर बिरोजा निस्सारण की अवधि, अपछेदों की संख्या, अपछेदों की लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए जारी किए गए निदेशों के अनुसार किया जाएगा:

आगे यह भी उपबन्धित है कि बांस गिराने कार्य 3 वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अन्तर्गत विनियमित किया जायेगा जो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और यह कि विक्रय बांसों के गिरान की आज्ञा भी सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा 3 वर्षीय गिरान कार्यक्रम के अनुसार दी जायेगी।

- (3) ऐसे क्षेत्रों से बाहर जाने वाला वन उत्पाद वनाधिकारी के निरीक्षण के अध्याधीन होगा और कोई भी वन उत्पाद किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्कासन के लिए प्राप्त लिखित आज्ञा होने पर भी, बिना निर्यात अनुवृत्ति के नहीं ले जाया जायेगा।

- (4) वन उत्पाद के निष्कासन की आज्ञा देने हेतु अधिकृत प्राधिकारी निष्कासन के लिए आज्ञा देते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो वन संरक्षण के हित में और इस प्रकार निष्कासित वन उत्पाद के दुरुपयोग के परिहार हेतु आवश्यक होगी।
- (5) उपरलिखित पैराग्राफों में समाविष्ट किसी बान के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी वृक्ष अथवा वृक्षों की श्रेणी का कटान या निष्कासन ऐसी शर्त के अध्याधीन जिसे यह जनहित में, जहां कहीं ऐसा करना उचित हो, अधिरोपित करना उचित समझे, को अनुमत करेगी जैसे कि नीतोड़ भूमि का अनुदान, जोतों की चकबन्दी अथवा सूखे गिरे वृक्षों अथवा 31-3-1979 से अनिर्णित पड़े हुए मामले।

हस्ताक्षरित/-
मन्त्रि (वन)।

FOREST FARMING AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION DEPARTMENT

ORDER

Simla-2, the 25th February, 1981

No. 15-4/71-SF-II.—Whereas, the State Government is satisfied, after due enquiry, under section 7 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 that regulations, restrictions, prohibitions or directions contained in this order are necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

2. Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 4 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978) is pleased to temporarily regulate, restrict and prohibit throughout the areas (except in Municipal Corporation/Municipal Committees, areas of other local bodies and areas falling in the peripheries of such local bodies) specified in the schedule annexed to Himachal Pradesh notification of even number dated 27-8-1980 in Kinnaur district the following acts for a period of 30 years with effect from the date of publication of this order in the Rajpatra Himachal Pradesh in the manner indicated below:—

1. The cutting of trees or timber and removal thereof in such areas shall be prohibited:

Provided that there will be no restriction on the use of forest produce for *bona fide* domestic purposes of fuel and fodder:

Provided further that the owners may for their *bona fide* domestic and agricultural use fell upto five trees each year without permission, up to 10 trees with written permission of the concerned Range Officer and more than 10 trees with written permission of the Divisional Forest officer concerned:

Provided further that the trees for sale shall be felled in accordance with the 10 years felling programme, which will be framed by the officers of the Forest Department and approved by the State Government subject to the condition that trees used for timber and other purposes will be felled after obtaining permission of the Divisional Forest Officer concerned upto 50 trees in a year, of the Conservator of Forests upto 100 trees in a year, of the Chief Conservator of Forests upto 200 trees in a year and of the State Government for more than 200 trees and that for other trees the permission will be accorded by the Divisional Forest Officer concerned in accordance with the 10 years felling programme:

Provided further that any person felling the trees either for domestic or agricultural use of for sale shall be required to plant at least 3 trees for one tree felled. In case, however, a fruit orchard is planted in such area, it shall be planted according to the norms laid down by the State Horticulture Department for complete stocking of the area.

2. Subject to the provisions of Para-1 the extraction, collection or removal or subjection to any manufacturing process of any forest produce in such areas shall be prohibited:

Provided that the extraction of resin will be undertaken with the written permission of the concerned Divisional Forest Officer in accordance with the instructions issued by the Chief Conservator of Forests from time to time laying down the period of extraction, number of blazes, length, width and depth of the blazes and other related matters:

Provided further that the felling of bamboos will be regulated according to 3 years felling programme, which will be framed by the officers of the Forest Department and approved by the State Government and that the permission for felling of bamboos for sale will be granted by the Divisional Forest Officers concerned in accordance with the 3 years felling programme.

3. The forest produce passing out of such areas shall be subject to examination by a forest officer and no forest produce will be removed by any person, even if it may have been extracted after obtaining permission aforesaid, without obtaining an export permit for the same.
4. The authority empowered to grant permission for extraction of forest produce may while grant permission impose such conditions as may be necessary in the interest of forest conservancy and to avoid mis-use of the forest produce so extracted.
5. Notwithstanding anything to the contrary contained in the foregoing paragraphs, the State Government may by general or special order allow the cutting or removal of any tree or class of trees subject to such condition as it may deem fit to impose wherever it is expedient to do so in the public interest such as grant of Nautor Land, Consolidation of Holdings or dry trees/fallen trees or in cases pending before 31-3-1979.

Sd/-
Secretary.